

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जार. श्री. स्वामीनाथन): (क) और (ख). 1979-80 के दौरान, केरल राज्य नियंत्रण समिति ने चूनोंदा पंचायतों में 46 अभियान आयोजित किए थे। स्थानीय समितियों ने लगभग 300 स्वयंसेवकों को कार्य पर लगाया था जिन्हें विषले जार के इस्तेमाल के बारे में प्रशिक्षण दिया गया था और उन्हें कृषि विभाग द्वारा मुफ्त रसायन-पदार्थ सप्लाई किए गये थे। किसान संघ, "सर्विस कोऑपरेटिव", किसान प्रशिक्षण केंद्र और केंद्रीय अन्न सुरक्षा अभियान दल ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया था और इसके व्यापक प्रचार की व्यवस्था की गई थी। यह कार्य लगभग 1.4 लाख मकानों और 1.6 लाख हेक्टर भूमि में हुआ। इसमें रसायन पदार्थों तथा प्रासंगिक खर्च के लिए 1.3 लाख रुपये खर्च हुए। ऊंचे लक्ष्य के साथ इस वर्ष भी इस योजना को जारी रखने का विचार है।

(ग) और (घ). केंद्रीय मूषक नियंत्रण सलाहकार बोर्ड ने कम्युनिटी आधार पर चूहों पर कारगर ढंग से नियंत्रण करने के लिए विभिन्न राज्यों में राज्य स्तर पर मूषक नियंत्रण समितियां गठित करने की सिफारिश की है। चूहा-कीट प्रबन्ध के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन विभिन्न संस्थाओं में राज्य के अधिकारियों के अधिकारियों को 'एपेक्स' स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजना के अधीन, धात्विक बिन, मंजूदा भण्डारण ढांचों में सुधार करने के लिए आदान तथा कीटनाशक दवाइयां सप्लाई करने और चूहों सहित विभिन्न कारणों से स्वास्थ्यों की क्षति को बचाने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता दी जा रही है। चूहों के नियंत्रण से संबंधित विशिष्ट कार्यों पर जोर देने के लिए प्रति वर्ष मूषक नियंत्रण सप्ताह का आयोजन किया जाता है।

Scarcity of Drinking Water in Orissa

*19. SHRI ARJUN SETHI:
SHRI K. PRADHANI:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the Central Government

are aware that there is acute scarcity of drinking water in drought affected villages of Orissa;

(b) whether the Government of Orissa has approached for the Central Government's help in this regard; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereon?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The Central Government's reaction is positive. The following assistance has been provided by the Central Govt. to the Govt. of Orissa:

(i) 10 rigs requested by the State Govt. to drill wells in hard rock areas have been supplied. It is proposed to supply six more rigs in the coming months.

(ii) A sum of Rs. 209 lakhs has been released as grant in the year 1979-80 under the Centrally sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme.

(iii) Advance Plan assistance as follows has been allocated for drinking water:

1979-80Rs. 300 lakhs

1980-81Rs. 200 lakhs

(iv) Guidance has been provided to the State Govt. in the preparation of Contingency Plan to cover all the villages. A check list has also been sent to the State Government.

(v) The concerned Ministries have been requested to make arrangements for hand pumps, pipes, cement, steel, etc. to be made available to the State Govt. on priority basis as and when required.

(vi) The State Government has also been advised to liaise with the Command Headquarters of the Ministry of Defence and seek assistance of the Army for storage, transportation, etc. of drinking water.